

पेज @ 3 राजस्थान सरकार ने अपना इकबाल दस माह में ही खो दिया : सचिन पायलट ...

पेज @ 4 जयपुर में केमिकल (इंडस्ट्रियल) डिजास्टर की राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का हुआ...

पेज @ 8 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली जिला कलक्टर्स की बैठक...

न्यूज़ अपडेट

अनंतनाग में अपहृत सेना के जवान की हत्या, शव बरामद, शरीर पर मिले गोलियों के निशान

अनंतनाग/एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंसा की घटना को अंजाम देते हुए प्रादेशिक सेना के एक जवान का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। सुरक्षाबलों ने जवान का शव बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आतंकवादियों ने जंगल के एक इलाके में गश्त पर निकले दो टीए जवानों को घेर लिया और उनका अपहरण कर लिया। हालांकि, इनमें से एक जवान आतंकवादियों के चंगुल से भाग निकलने में सफल रहा। शेष बचे जवान की तलाश में सुरक्षाबलों ने तत्काल एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। गहन खोज के बाद जवान का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में शव पर गोली के निशान पाए गए हैं।

जातीय हिंसा से प्रभावित 2,072 किसानों को मुआवजा देगी मणिपुर सरकार

इंफाल/एजेंसी। मणिपुर सरकार ने राज्य में 17 महीने से चल रहे जातीय संघर्ष से प्रभावित 2,072 किसानों को 13.3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की रिफारिश पर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कानून व्यवस्था संकट से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के अनुसार, इस धनराशि से क्षतिपूर्ति फसल पैकेज के दूसरे चरण के अंतर्गत 2,072 किसानों को राहत मिलेगी। राज्य के आयुक्त (गृह) एन. अशोक कुमार ने एक अधिसूचना में कहा कि इस जातीय संकट के दौरान किसानों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राइजिंग राजस्थान के संबंध में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक

पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

चमकता राजस्थान

जयपुर, 10 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से राजस्थान में उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी तथा सभी के सहयोग से इस समिट को सफल बनाते हुए राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान के संबंध में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में विपुल प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के चलते निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे। हमने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट करने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी बन सके।



बिजली, पानी तथा आधारभूत संरचना राज्य सरकार की प्राथमिकता

शर्मा ने कहा कि बिजली, पानी तथा आधारभूत संरचना का योजनाबद्ध तरीके से विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जो हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी असीमित संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में 53 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क और नौ ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेस वे विकसित करने की योजना भी बनाई गई है, जिनसे निवेशकों को और अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र भी प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे हैं।

सीए-सीएस राज्य की बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीए-सीएस सहित अन्य प्रोफेशनल्स राज्य की बड़ी ताकत हैं। इन प्रोफेशनल्स की विश्वसनीयता रहती है तथा ये सरकार व उद्यमियों के हित में काम करते हैं। उन्होंने आशा जताई कि प्रोफेशनल्स राज्य को निवेश का हब बनाने तथा अधिक से अधिक निवेश लाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के सीए और सीएस अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थानी जहां भी रहते हैं, खुशहाली लाते हैं, आगे बढ़ते हैं और सभी को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थानी प्रत्येक जगह पर अपनी कर्मठता से पहचान बनाते हैं।

राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए हमारी टीम दिन रात काम में जुटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए हमारी टीम दिन-रात काम में जुटी हुई है। हमने नवनियुक्त आईएएस ऑफिसर को आयोजन के लिए नियुक्त किया है। साथ ही, देशभर में राजस्थान मूल के आईएएस अफसर, भूतपूर्व आईएएस अफसरों सहित सभी वर्गों से भी इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है।

राइजिंग राजस्थान में हम पूरा सहयोग देंगे- उद्यमी

बैठक में आए उद्योगपतियों एवं प्रोफेशनल्स ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए हम सभी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहभागिता करेंगे तथा आयोजन को सफल बनाते हुए राज्य में निवेश लाने में पूरा सहयोग करेंगे। उद्योगपतियों ने युवाओं में उद्योग परक कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने, फिन्टेक को प्रोत्साहित करने, निवेश को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग, स्टार्ट अप को प्रमोट करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए। इस दौरान खनन, रियल एस्टेट, हैडीक्राफ्ट, सीए, मेडिकल डिवाइस, शिक्षा, फर्नीचर सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मशहूर उद्योगपति टाटा समूह के चेयरमैन स्व. रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव विल अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, जिनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन आई सी अग्रवाल, एअरजी ग्रुप के चेयरमैन आत्मा राम गुप्ता, सीएस इन्स्टीट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल, सीए इन्स्टीट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गायल, गोलचा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन विक्रम गोलचा, महर्षि अरविंद युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजय पाराशर, पॉली मेडिकेयर के अध्यक्ष विशाल बेद, मचेंट बैंकर अशोक होलानी, सीए नरेन्द्र मितल, सीए प्रकाश शर्मा, सीए पीपी पारीक सहित विभिन्न उद्योगपति एवं सीए-सीएस मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक

1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर करें कार्य : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- समान पदों पर समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में एकरूपता लाने के निर्देश
- समय, संसाधनों और श्रम का सदुपयोग करते हुए एकसाथ आयोजित करें छोटी भर्तियां



न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों का समय पर हो निस्तारण

शर्मा ने कहा कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने विभिन्न कारणों से न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों में विभागों की ओर से प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिए, ताकि इन प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केन्द्र विकसित किए जाएं तथा वहां सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हों। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अरुणा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

भर्तियों में तेजी लाने के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी

मुख्यमंत्री ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कमेटी भर्तियों में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एकसाथ आयोजित करने पर भी विचार करें। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि एक जैसे पदों के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे समय, संसाधनों और श्रम का नुकसान होता है। साथ ही, अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इसे देखते हुए समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण तथा एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री मोदी वियनतियाने के लिए रवाना

कहा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से बहुत लाभ हुआ



नई दिल्ली/एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आसियान-भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को लाओ पीडीआर के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यह वर्ष विशेष है क्योंकि यह भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक का प्रतीक है जिससे देश को बहुत लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और विश्व नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। मोदी ने कहा कि 21वें आसियान-भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक दशक पूर्ण कर रहे हैं। मैं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और हमारे सहयोग की भावी दिशा तय करने के लिए आसियान नेताओं के साथ शामिल होऊंगा।

